India had brought it to the notice of the Burmese Government.

MR. SPEAKER : Next question.

उत्तर प्रदेश के लिये धन

*1565. **श्री मोलहू प्रसाद** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटेल आयोग द्वारा किये गये नमूना सर्वेक्षण की सिफारिशों के आधार पर केन्द्रीय सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को कोई धनराशि दी गई है तथा उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ धन पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास कार्यों पर खर्च किया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक केन्द्रीय सरकार द्वारा कितना धन नियत किया गया है तथा राज्य सरकार ने कितने धन का अंशदान दिया है; और

(ग) पटेल आयोग की सिफारिशों के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश के किन-किन जिलों में उक्त धनराशि खर्च की जायगी तथा कुल धनराशि में से कितनी धनराशि गोरखपुर में खर्च की जायेगी ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है। [**पुस्तकालय में रखा गया**। **देखिये संख्या** LT—1113/68]

श्री मोलहू प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, यह जो विवरण सभा-पटल पर रखा गया है, इस में प्रधान मन्त्री जी ने बताया है कि केन्द्र द्वारा 1964-65 में 4 करोड़ रुपये, 1965-66 में 4.5 करोड़ रुपये तथा राज्य सरकार की तरफ से 1964-65 में 7.04 करोड़ रुपये और 1965-66 में 7.52 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं। 1966-67 में 15.55 करोड़ रुपये व्यय किये गये हैं। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि यह धनराशि किन-किन मदों में खर्च की गई है तथा 1967-68 में जो 13.97 करोड़ रुपये खर्च किये जाने का अनुमान है, वह किन-किन मदों पर खर्च किया जायगा ?

श्री ब० रा० भगत : यह धनराशि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, माइनर इरिगेशन, सायल-कन्जर्वेशन, एनीमल हसबैंड्री, कोआपरेटिव्ज, कम्यूनिटी डेवेलपमेन्ट आदि पर व्यय की जायेगी।

श्री मोलहू प्रसाद : मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि पटेल आयोग ने जो अध्ययन किया था, उस की सिफारिश के अनुसार गाजीपुर, आजमगढ़, देवरिया तथा जौनपुर - इन चार जिलों को शामिल किया गया था, लेकिन राज्य सरकार की सिफारिश पर बलिया तथा बस्ती के दो जिले और शामिल कर लिये गये थे। मैं जानना चाहता हूं कि गोरखपुर तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों को शामिल न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री ब० रा० भगत : इस में सन्देह नहीं है कि और भी कई जिले अर्धविकसित या अविकसित रूप में हैं, लेकिन यह जो कार्य हुआ था, खास तौर से एक्सपेरिमेन्टेशन के तौर पर हुआ था। शुरू में चार जिलों को लिया गया था, लेकिन राज्य सरकार ने दो जिले और शामिल कर दिये थे। अब जो चौथी योजना बनेगी, उस में सारे ऐसे इलाकों का डिस्ट्रिक्ट बेसिज पर इन्टीग्रेटेड डेवेलपमेन्ट होगा, उस में ये सारे जिले लिये जायेंगे।

श्री मोलहू प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में इस समय कोई सरकार नहीं है, वहां का शासन आपके हाथ में है तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप इन जिलों में पटेल आयोग की सिफारिश को लागू करने के लिये तैयार हैं ?

श्री ब० रा० भगत : सरकार तो वहां पर है, ऐसी बात नहीं है कि वहां कोई सरकार नहीं

है। किसी पार्टी के हाथ में सरकार नहीं है, प्रेसीडेन्ट रूल है।

श्री मधु लिमये : आपके नियन्त्रण में है।

श्री ब० रा० भगत : अभी जो चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार हुआ है उसमें इस बात की कोशिश की जा रही है कि जिलों की समस्याओं को दूर करने और उनका आर्थिक विकास करने के आधार पर प्लान बने। उसमें इन बातों का खयाल किया जायेगा।

SHRIMATI SUSHILA ROHATGI : Seeing that the *per capita* investment in UP has been the lowest in the country, that UP is one Plan behind the other States, and also that U. P. has the highest populace to feed in the country and also being aware of the fact that the country's economy must progress simultaneously in all the States together, would the Government consider that it gave all-out assistance to UP in the implementation of the Patel Commission's recommendations ?

SHRI B. R. BHAGAT : If the hon. Member means Central assistance, yes, because in Central assistance population, *per capita* consumption and investment is looked into. But in pulling out any State or area from economic back wardness and taking it to a higher rate of growth, Central assistance plays only a marginal role and the bulk of the effort, human, material and financial, therefore, has to come from the States themselves.

श्री रामजी राम : मैं जानना चाहता हूँ कि पटेल आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत फैजाबाद जिले को भी लिया जायेगा क्योंकि फैजाबाद जिले की जो स्थिति है वह पूर्वी जिलों से भी बदतर है ?

श्री ब० रा० भगत : जैसा मैंने कहा, पटेल आयोग ने सिफारिशी तौर पर, ऐसे जिले जो अविकसित हैं वहां आर्थिक विकास जल्दी हो सके, उसके लिये तरीके बतलाये थे। उसकी शुरुआत 6 जिलों में हुई है और जैसा मैंने बतलाया चौथी योजना से और जिलों में इसको फैलाया जायेगा।

श्री नाथूराम अहिरवार : मैं जानना चाहता हूं कि चूंकि मध्य प्रदेश भी एक बहुत ही पिछड़ा प्रान्त है और उसके कुछ इलाके...

अध्यक्ष महोदय : यह उत्तर प्रदेश का क्वैश्चन है, मध्य प्रदेश का नहीं है।

श्री बैं० ना० कुरील : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि इसी अप्रैल महीने की 12 तारीख को उत्तर प्रदेश के गवर्नर महोदय ने इस आशय का एक प्रतिवेदन प्रधान मन्त्री जी को दिया है कि उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री ब० रा० भगत : जी हां, दिया है और उस पर विचार किया जा रहा है।

श्री शिव नारायण : अध्यक्ष महोदय, मुझे भी एक बहुत जरूरी सवाल करना है। श्री टी० टी० कृष्णमाचारी यहां फाइनेन्स मिनिस्टर थे तब उन से एप्रोच करके यह हुआ था लेकिन अब वह सारी स्कीम बन्द है। जैसा कि भगतजी ने जवाब दिया, मैं बताना चाहता हूँ कि वहां पर कोई काम नहीं हो रहा है। चार जिलों में कोई काम नहीं हुआ। बलिया और बस्ती में भी नहीं हुआ। मेरा कहना यह है कि यह आपकी रेस्पांसिबिलिटी है, सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट का वहां पर कन्ट्रोल है क्योंकि प्रेसीडेन्ट रूल लागू है, तो फिर आप ही अपनी ओर से इस काम को क्यों नहीं शुरू करवा दें। वह इलाका सबसे गरीब है और वह टोटली नेग्लेक्टेड है इस गवर्नमेंन्ट में भी, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुरन्त ऐक्शन लिया जाये और सरकार की तरफ से पक्का एश्योरेन्स दिया जाये क्योंकि वहां पर माइनर इरीगेशन का काम रुका हुआ है।

श्री ब० रा० भगत : ऐसी बात नहीं है कि वहां पर काम बन्द है। 67-68 में 14 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है। हां, यह बात सही है कि जिस तेजी से काम होना चाहिये, उस तेजी से काम नहीं हो रहा है। चूंकि सारे प्लान्स स्टेट गवर्नमेन्ट के हैं और जहां पूंजी इकट्ठी नहीं हो सकी वहां पर प्लान कम हो गया। ...(**व्यवधान**)...

SHRI R. K. SINHA : The blueprints for the Fourth Five Year Plan are going to be finalised soon. There is no elected government in Utter Pradesh. I have all faith but I am not quite sure : unless people's representatives are associated with the finalisation of the Fourth Five Year Plan, Utter pradesh may again be an industrial desert as it has been so far. Will the Government of India examine the possibility whether those people, who have been nominated to the Governors advisory council for Parliament could be associated with the finalaisation of the Fourth Five Year Plan for Utter Pradesh ?

SHRI B. R. BHAGAT : Yes, Sir ; this is a good suggestion which we may consider.

श्री जागेश्वर यादव : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश का जो बुन्देलखंड का क्षेत्र है, झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा, इन जिलों का कोई विकास नहीं किया जा रहा है। न तो वहां पर सड़कों का विकास हुआ है और न सिंचाई के साधन, जैसे ट्यूबवेल वगैरह हैं, उनका ही विकास हुआ है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास इन जिलों के विकास के लिये भी कोई योजना है ?

श्री ब० रा० भगत : जी, हां, यू० पी० का जो स्टेट प्लान है उसमें बुन्देलखंड के जिलों के विकास की भी योजना है।

संसद सदस्यों के लिये अस्त्र

+

*1566. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री जमुना लाल :

क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संसद् सदस्यों को अपनी रक्षा के लिये रियायती दरों पर कुछ अस्त्र देने की कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में कौन सी योजना बनाने का विचार है ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTERY OF DEFENCE (SHRI M. R. KRISHNA) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) No such proposal is under the consideration of Government at present.

श्री ओंकार लाल बेरवा : अध्यक्ष महोदय, पहले लोक-सभा के सदस्य होते हैं और बाद में मन्त्री बनते हैं। जितने भी मन्त्री, उप मन्त्री और राज्य मन्त्री हैं उनके यहां तो हमारे खर्चे से पहरा लगा रहता है, पहरेदार बन्दूक लगाये खड़े रहते हैं लेकिन संसद सदस्यों के दरवाजे पर कुत्ता भी नहीं रहता है और उनकी रक्षा के लिये सरकार ने कोई योजना नहीं बनाई। रेल के अन्दर, एक माननीय सदस्य यहां बैठे हैं, उनकी घड़ी और नोट ले लिये गये। एक डाक्टर साहब थे, पिछले टाइम में, उनको मारने की धमकी दी गई और औरतों की चूड़ियां उतार ली गई। इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने कोई ऐसी योजना बनाई है जिसके अन्तर्गत संसद सदस्यों को फिक्स्ड प्राइस पर अस्त्र मिल सकें ? वे अपने पैसे से खरीद लेंगे।

SHRI M. R. KRISHNA : In the firist place, it is not true that evrry minister is protected with armed guards. Secondly, if you and the Minister of Parliamantary Affairs... (*Interruption*)

MR. SPEAKER : Do not drag in the Speaker. What you do is your concern... (*Interruption*)

SHRI M. R. KRISHNA : If the Minister of Parliamentary Affairs and you feel that Members of Parliment are physically weak to defend themselves, you and the Parliamentary Affairs, Minister may decide that along with facilities which